under the provision of the Insecticides Act, 1968, like acephate, chlorpyriphos, endosulfan monocrotophos, phentheate, phosalone, phosphamidon for the control of American Bollworm on cotton crop. They were also advised to drain out the excess rain water from their fields to mitigate the affect of water logging. There is no proposal under consideration of the Central Govt. to give compensation to farmers for loss of the cotton crop.

Loss of Paddy Crop in Eastern Uttar Pradesh

313. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are planning to conduct a survey of the paddy crop which suffered heavy loss due to a dangerous disease in Eastern Uttar Pradesh, particularly in Ballia and Mau districts;

(b) whether it is also a fact that a large number of farmers have been forced to burn their paddy crop due to this disease;

(c) if so, the steps taken or likely to be taken prevent this disease and compensate farmers; and

(d) if not, the reasons therefor, with details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (d) Regular survey of paddy and other crops is carried out by the Central and State Governments to monitor the pest and disease situation. No specific report has been received about any dangerous disease in Eastern Uttar Pradesh so far. However, a study would be conducted particularly in Bhallia and Mau districts to assess the disease, its impact and remedial measures required at an early date.

अनुपजाऊ भूमि की स्थिति

314. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत बड़ा भू-भाग अनुपजाऊ है जिसके परिणाम स्वरूप उस भूमि से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की भूमि का समुचित उपयोग करने के लिए कोई रणनीति बनाई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि और सहकारिता विभाग ने देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में निम्नीकृत भूमि का उत्पादकता को बेहतर बनाने हेतु इसके उपचार के लिए नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, क्षारीय मृदा का सुधार नामक योजनाएं तथा झूम खेती वाले क्षेत्रों में जल विकास परियोजना नामक विभिन्न केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं। गहरी व तंग घाटी क्षेत्रों का सुधार और प्रबंध संबंधी कार्यक्रम भी इस विभाग में शुरू किया गया था परन्तु राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से क्षारीय मृदा के सुधार तथा विकास पर एक अन्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, बंजड़ भूमि विभाग, समेकित बंजड़ भूमि विकास की योजना कार्यान्वित करता है। 1996-97 तक 1362.11 करोड़ रुपए के व्यय से 54.06 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है।

गोदुग्ध उत्पादन में कमी आना

315. **श्री नागमणि:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गोदुग्ध उत्पादन में हर वर्ष कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं। गाय के दुध का

उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। वर्ष 1992-95 के लिए उत्पादन निम्नानुसार है:—

1992-93	243.4 लाख मीटरी टन
1993-94	253.4 लाख मीटरी टन
1994-95	265.2 लाख मीटरी टन

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब के किसानों को बीजों तथा दालों के संबंध में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराया जाना

316. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95,1995-96 तथा 1996-97 के दौरान पंजाब राज्य के किसानों को अच्छी किस्म के बीजों तथा दालों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान पंजाब राज्य को विभिन्न फसल उत्पादनोन्मुखी योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में कुल 970.488 लाख रुपए का आबंटन किया गया ताकि बीजों के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जा सके। तथापि, राज्य ने केवल 567.379 लाख रुपए का उपयोग किए जाने की सूचना दी है।

इसी अवधि के दौरान दलहन विकास के लिए, जिसमें बीज वितरण के लिए सहायता भी शामिल है, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में कुल 82.00 लाख रुपए का आबंटन किया गया है। सूचित किया गया है कि राज्य ने इसमें से 60.31 लाख रुपए का उपयोग कर लिया है।

Production of Cotton

317. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the production of cotton during 1990-91 to 1996-97, State-wise;

(b) the target set to raise the production of cotton by the end of Ninth Five Year Plan, alongwith the total area likely to be covered under the cotton cultivation during this plan; and

(c) the action being taken by Government to increase the production of cotton in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) A statement giving State-wise estimates of production of cotton for the period 1990-91 to 1996-97 is given in the statement (*See* below)

(b) The target of production of cotton for the 9th Plan are yet to be finalised by the Planning Commission. The area targets are, however, not fixed.

(c) To increase the production and productivity of the cotton, the Government is implementing a Centrally Sponsored Scheme of Itensive Cotton Development Programme is eleven major cotton producing States of the country. Assistance under the scheme is being provided for production of breeder, foundation and certified seeds, distribution of certified seeds, demonstration and training, distribution of plant protection equipments, supply of sprinklers etc.